भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 485

06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी नियोजन में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण

485. श्री मनोज तिवारीः
श्री अनुराग शर्माः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री भोजराज नागः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री तापिर गावः
श्री महेश कश्यपः
श्री बलभद्र माझीः
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार किस प्रकार उन्नत स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए शहरी कार्यबल के भविष्य की कल्पना करती है;

(ख) क्या शहरी नियोजन भूमिकाओं में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोई विशिष्ट कार्यक्रम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय) और राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किन शहरों को शामिल किया गया है और आज तक उन शहरों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून 2015 को शुरू किए गए अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को कार्यान्वित कर रहा है। स्मार्ट

तत्व, घटक और प्रौद्योगिकियाँ अमृत परियोजनाओं का हिस्सा हैं और इसका उद्देश्य सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना है। अमृत दिशा-निर्देश जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं के हिस्से के रूप में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) जैसे स्मार्ट तत्वों का प्रावधान करते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एससीएडीए के साथ 230 जल आपूर्ति परियोजनाएँ और 146 सीवरेज परियोजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं।

स्टार्ट-अप विचारों और निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और उन्हें पायलट परियोजनाओं में शामिल करने वाला प्रौद्योगिकी उप-मिशन अमृत 2.0 का एक महत्वपूर्ण घटक है। अमृत 2.0 के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 1482 जलापूर्ति परियोजनाओं, 241 सीवरेज परियोजनाओं को एससीएडीए के साथ मंजूरी दी गई है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के पदाधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि की क्षमता में सुधार के लिए मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के माध्यम से क्षमता निर्माण गतिविधियों में राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें महिलाओं सहित समाज के सभी वर्ग शामिल हैं। अमृत के तहत, 45000 पदाधिकारियों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 57134 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत ठेकेदारों, प्लंबरों, संयंत्र संचालकों, छात्रों, महिलाओं और नागरिकों सहित सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में 4 संस्थानों को शहरी नियोजन एवं डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नामित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ सिविल सेवकों, राज्य नगर नियोजकों, नगर निगम अधिकारियों, व्यवसायियों/पेशेवरों, युवा छात्रों आदि को प्रमाणित प्रशिक्षण/प्रमाणित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। इन केंद्रों में से प्रत्येक को 250 करोड़ रुपये की बंदोबस्ती निधि प्रदान की गई है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने क्षमता निर्माण के लिए शहरी नियोजन के अमृत वित्तपोषित केंद्र के रूप में 6 संस्थानों को भी नामित किया है। इन संस्थानों की भूमिका में नगरपालिका अधिकारियों/नगर एवं ग्राम नियोजन अधिकारियों को विषय-विशिष्ट प्रशिक्षण देना, राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों के क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना तथा शहरी नियोजन में उनकी सहायता करना शामिल है।

अमृत 2.0 के तहत मंत्रालय ने अमृत मित्र पहल भी शुरू की है, जिसमें जल मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता परीक्षण, जल अवसंरचना संचालन और अन्य जल क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं में महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को शामिल किया गया है। इस पहल के तहत अब तक 140 करोड़ रुपये की लागत वाली 1762 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

(ग) भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं संवर्धन योजना (हृदय) 21 जनवरी, 2015 को शुरू की गई थी और इसे बारह शहरों में लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ का कोई भी शहर इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं था। यह मिशन 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गया है और 31 मार्च, 2019 के बाद कोई भी नई परियोजना/शहर शुरू नहीं किया गया।

स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य से 3 शहरों अटल नगर, बिलासपुर और रायपुर का चयन किया गया है। एससीएम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्मार्ट शहरों को कुल 1351.63 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें अटल नगर को 488 करोड़ रुपये बिलासपुर को 428.75 करोड़ रुपये और रायपुर को 434.88 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

*****